



The Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967

Act 16 of 1967

Keyword(s):

Compensatory Allowances, Prevention of Disqualification

Amendments appended: 30 of 2006, 8 of 2019, 22 of 2019, 16 of 2021, 16 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९६७

मध्यप्रदेश विधान सभल सदस्य निरहंता निवारण अधिनियम, १९६७

दिनांक १८ जुलाई १९६७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक १७ जुलाई १९६७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।

कतिपय लाभ के पदों को, उनके धारकों को राज्य विधान सभल के सदस्य चुने जाने या होने के लिये निरहंत न बनाने वाले घोषित करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान सभल द्वारा इसे निम्न-लिखित रूप में अधिनियमित किया जाय।

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभल सदस्य निरहंता निवारण अधिनियम, १९६७ कहा जा सकेगा।

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "समिति" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो;
- (ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड, कम्पनी, सोसायटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो।

३. (१) कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश विधान सभा या मध्यप्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण ही निरहंत नहीं होगा कि वह सरकार के अधीन लाभ के पदों में से, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई भी पद धारण करता है।

(२) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी समिति के सभापति या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय मध्यप्रदेश विधान सभा या मध्यप्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या होने के लिये केवल इस तथ्य के कारण निरहंत नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है।

परन्तु किसी ऐसे पद के धारक को निम्नलिखित से अनधिक यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते से भिन्न कोई फीस, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं मिलता हो—

- (एक) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य न हो, तो राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के आफिसर के लिये स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता, और

(200)

संविधान सभा द्वारा दिनांक १३ अक्टूबर १९४७

२१८७

(बो.) यदि ऐसा भारत सरकार विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, तो सोनी समा के सदस्य या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य के लिये, प्राप्ति किये गये पद के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होने की दशा के अनुसार, स्वीकार्य मात्रा मता तथा दैनिक भत्ता.

४. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन प्रॉफ डिस्कवालीफिकेशन निरसन. एक्ट, १९५६ (क्रमांक १ सन् १९५७) एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा ३ (१) देखिये]

१. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.
२. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति.
३. राज्य मंत्री.
४. उप-मंत्री.
५. संसदीय सचिव.
६. महाधिवक्ता.
७. सरकारी प्लीडर.
८. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८६८ (क्रमांक ५ सन् १८६८) में यथापरिभाषित लोक अभियोजक.
९. मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५६ (क्रमांक २० सन् १९५६) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में भूमी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति.
१०. प्रॉविन्शियल इन्साल्वेंसी एक्ट, १९२० (क्रमांक ५ सन् १९२०) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसीवर.
११. मध्यप्रदेश इर्रिगेशन एक्ट, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१) की धारा ६२ के अधीन बनाये गये नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच.
१२. नेशनल क्रेडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद.
१३. रिजर्व एंड प्रॉक्सीली एयर फोर्स एक्ट, १९५२ (क्रमांक ६२ सन् १९५२) के अधीन स्थापित की गई प्रॉक्सीली एयर फोर्स या एयर डि हेंस रिजर्व का कोई भी पद.
१४. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक २६ अक्टूबर, सन् १९६२ के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किसी अन्य सशस्त्र दलों के कृत्य.

3

समन्वयित कारखाना, दिल्ली १५ जुलाई १९६७

१५. ऐसे बीमारुता को भोजन मिले कि नियंत्रित कारखाना का प्रबंध साइकल हन्डोरेस (इमर्जेंसी प्रावीजन्स) एक्ट, १९४६ (क्रमांक ६ सन् १९४६) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निर्मित हो। कोई भी मद.

व्याख्या :—मद १५ के प्रयोजन के लिए 'बीमारुता' तथा 'नियंत्रित कारखाना' के वही अर्थ होंगे जो कि साइकल हन्डोरेस (इमर्जेंसी प्रावीजन्स) एक्ट, १९४६ (क्रमांक ६ सन् १९४६) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किये गये हैं.

भोपाल, दिनांक १७ जुलाई १९६७.

क्र. २२४२३-इक्वीस-थ (प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसार समन्वयित विधान मण्डल सदस्य निर्वाचन विधायन अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) के अधीन अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रे. शं. त्रिवेदी, सचिव.

(290)

मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या १६ १९६७

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 1967

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA
NIRHATA NIVARAN ADHINIYAM 1967.**

[Assent of the Governor on the 14th July 1967, assent first
published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary on the 17th
July, 1967.]

**Enact to declare certain offices of the profit not to disqualify
their holders for being chosen as or for being members of
the State Legislature.**

**Enacted by the Madhya Pradesh Legislature in
the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:—**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Short title.
Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— **Definitions.**

(a) "Committee" means any committee, council,
board or any other body of persons whether
a statutory body or not set up by the Central
Government or any State Government;

(b) "Statutory body" means any corporation, board,
company, society or any other body of persons,
whether incorporated or not, established,
registered or formed by or under any law for
the time being in force or exercising powers
and functions under any such law.

3. (1) A person shall not be disqualified for being **Prevention of**
chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh **disqualification**
Legislative Assembly or the Madhya Pradesh Legislative
Council by reason only of the fact that he holds any of the
offices of profit under Government specified in the Schedule.

Explanation

(2) No person, holding the office of the Chairman or
member of any committee, shall be disqualified at any time
for being chosen as, or for being, a member of the Madhya
Pradesh Legislative Assembly or the Madhya Pradesh
Legislative Council by reason only of the fact that he holds
such office.

Provided that the holder of any such office is not in
receipt of any fee, allowances or remuneration other than
travelling or daily allowances not exceeding—

(i) the travelling allowance and daily allowance
admissible to a first-grade officer, serving

Subst. by M. P. Act No 26 of 1973
Subst. by M. P. Act No 29 of 1971

under the State Government, if such holder is not a member of the said Legislative Assembly or the Legislative Council, and

- (ii) the travelling allowance and daily allowance admissible to a member of the House of People or a member of the State Legislative Assembly the State Legislative Council according as the office held is under the control of the Central Government or the State Government, if such holder is a member of the said Legislative Assembly or Legislative Council.

4. The Madhya Pradesh Legislative Assembly Prevention of Disqualification Act, 1956 (1 of 1957) is hereby repealed.

THE SCHEDULE

List of Offices of profit under Government.

[Vide section 3(1)]

Repeal.

1. Speaker and Deputy Speaker of the State Legislative Assembly.
2. Chairman and Deputy Chairman of the State Legislative Council.
3. Minister of State.
4. Deputy Minister.
5. Parliamentary Secretary.
6. Advocate General.
7. Government Pleader.
8. Public Prosecutor as defined in the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).
9. Any person appointed as, or performing the functions of, a Patel under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959) or a Manjhi or a Chalki in Bastar District.
10. Official Receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (V of 1920).
11. Sarpanch of an irrigation panchayat as defined in the rules made under section 62 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (III of 1931).
12. Any office in the National Cadet Corps or the Territorial Army.

संघस्य प्रवेशादयः विनाशः १७ जुलाई १९६०

२१६१

13. Any office in the Auxilliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserved and Auxilliary Air Forces Act, 1952 (LXII of 1952).
14. Member of the naval, military, air forces or any other armed forces of the Union during the period, the proclamation of Emergency by the President of India, dated the 26th October, 1962, remains in force and six months thereafter.
15. Any office under an insurer the management of whose controlled business is vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (IX of 1956).

Explanation.—For the purpose of item 15 "insurer" and "controlled business" shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (IX of 1956).

- 1- 16 Added —
- 17-
- 2- 18- Added - 1

- 1- Added by m.p. No 108 of 1973
- 2- Added by m.p. No 108 of 1974

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
मूल्य के लिये भुगतान (बिना डाक
चार्ज) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. १२-छत्तीसगढ़ गजट/३८ सि. हे.
मिलाइ, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114 009/2003/29 1-03."

कार्य क्रमांक

दिनांक-

922

148/सं.का./200

12/12/06

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1003

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2006 (अवकाश 14, शक 1928)

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 04-12-06 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एवं इदाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 30 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006.

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम 1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य तथा प्रारंभ निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा.

परिभाषा 2. इस अधिनियम में, "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967).

धारा 2 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ग) "प्रतिकर भत्ता" से अभिप्रेत है, किसी पदधारी को पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, बैठक शुल्क, वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, संचार भत्ता या अन्य कोई भत्ते के रूप में देय कोई धन राशि."

धारा 3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"3. कतिपय लाभ के पद निरर्हकारी नहीं
एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी पद, जहाँ तक वह शासन के अंतर्गत लाभ

का पद है, उसके धारक को छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा या कमी भी निरर्हित नहीं किया गया है, माना जाएगा.

139

- 3-क. कतिपय पदों की निरर्हता का प्रतिषेध धारा 3 के उपबंधों के अध्याधीन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए मात्र इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है।

परन्तु किसी ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता हो।”

अनुसूची का 5. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—
संशोधन

(एक) मद 8 में शब्द, अंक तथा कोष्ठक “ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का सं० पांच)” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं० दो) ” स्थापित किए जाएं,

(दो) मद 18 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“18. मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत से धारित पद.

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद:—

(1)	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति.
(2)	राज्य श्रोत (निःशक्तजन) संस्थान.
(3)	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड.
(4)	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गठित राज्य स्तरीय समिति एवं मूल्यांकन समिति.

(5)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्.
(6)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण.
(7)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी.
(8)	छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
(9)	शासकीय किरोड़ीमल पॉलीटेक्निक सोसायटी, रायगढ़.
(10)	कार्यकारी समिति, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.
(11)	राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़.
(12)	राज्य शिक्षता परिषद्, छत्तीसगढ़.
(13)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क0 21 सन् 1994) के अधीन गठित स्थायी समिति.
(14)	छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सर्तकता तथा मॉनिटरिंग कमेटी.
(15)	छत्तीसगढ़ आदिग जाति मंत्रणा परिषद् (जनजाति सलाहकार परिषद्).
(16)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल.
(17)	छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड.
(18)	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी (कंडा)
(19)	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(20)	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड.
(21)	राज्य उद्योग सलाहकार मण्डल.
(22)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(23)	सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
(24)	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.
(25)	राज्य योजना मंडल.
(26)	छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स).
(27)	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन.
(28)	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड.
(29)	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(30)	छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
(31)	छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल भारत स्काउट एण्ड गाइड.
(32)	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का परियोजना सलाहकार मण्डल.
(33)	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
(34)	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल.
(35)	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड.

(36)	छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम
(37)	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(38)	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
(39)	छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित
(40)	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड
(41)	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल
(42)	छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद्
(43)	विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 166(4) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समन्वय फोरम
(44)	छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी0बी0डी0ए0)
(45)	राज्य जल स्थायी समिति
(46)	राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड
(47)	स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर
(48)	स्वशासी समिति, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
(49)	स्वशासी समिति, पं० जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
(50)	स्वशासी समिति आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर
(51)	छत्तीसगढ़ पैरा-मेडिकल कौंसिल, रायपुर
(52)	राज्य स्वास्थ्य मिशन
(53)	छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
(54)	कुष्ठ रोग नियंत्रण समिति
(55)	मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण समिति
(56)	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समिति
(57)	क्षय रोग नियंत्रण समिति
(58)	प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति
(59)	बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान रायपुर
(60)	छत्तीसगढ़ पर्यटन सलाहकार बोर्ड
(61)	होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर
(62)	छत्तीसगढ़ महिला कोष
(63)	राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़
(64)	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग
(65)	छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम
(66)	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड
(67)	छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत बोर्ड
(68)	छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
(69)	छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन
(70)	राज्य शहरी विकास अभिकरण

(71)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड.
(72)	छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.
(73)	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड.
(74)	छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम.
(75)	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड.
(76)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.
(77)	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.
(78)	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
(79)	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
(80)	छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग.
(81)	छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग.
(82)	छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायपुर.
(83)	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित.
(84)	श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी सम्पदा समिति (न्यास), राजनांदगांव.
(85)	छत्तीसगढ़ संवाद.
(86)	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम.
(87)	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित
(88)	छत्तीसगढ़ राज्य वन्य प्राणी बोर्ड.
(89)	छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड.
(90)	शासकीय चिकित्सालय की जीवन दीप समिति."

विधि मान्यकरण 6.
के संबंध में
विशेष प्रावधान.

- (1) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या मत के होते हुए भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद उनके धारकों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए उसी तरह निरहित नहीं करेंगे या ऐसे पदों द्वारा उनके धारकों को कभी भी निरहित नहीं किया गया है, यह उसी तरह माना जाएगा जैसे कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित रूप में मूल अधिनियम सभी सारवान समय में प्रवृत्त रहा था.
- (2) शंकाओं के निराकरण हेतु एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी याजिका या संदर्भ का निराकरण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 30 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force retrospectively with effect from 1st November, 2000.

Definition 2. In this Act, "Principal Act" means the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No.16 of 1967).

Amendment of Section 2 3. After clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely:-

"(c) "Compensatory Allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance, house rent allowance, communication allowance or any other allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office."

Amendment of Section 3 4. For Section 3 of the Principal Act, the following Sections shall be substituted, namely,

"3. **Certain offices of profit not to disqualify**

It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule, in so far as it is an office of profit under the Government, shall disqualify or shall be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

**3-A. Prevention of
disqualification
of certain offices**

Subject to the provisions of Section 3 no person holding the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director or Member of any committee shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds such office:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any remuneration other than compensatory allowance."

**Amendment of
Schedule.**

5. In the Schedule to the Principal Act:-

- (i) in item 8, for the words, figures, and bracket "Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898)" the words, figures and bracket "Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974)" shall be substituted.
- (ii) For items 18 to 22, the following items shall be substituted, namely:-

"18. the office held by Chief Minister or Minister or Minister of State or Deputy Minister in ex-officio capacity.

19. the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director and Managing Director or Member Secretary or Secretary or Member of the following statutory body or committee: -

(1)	State Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995.
(2)	Rajya Shrot (Nishaktjan) Sansthan.
(3)	State Advisory Board constituted under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
(4)	State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted for Rural Development Programme.
(5)	Chhattisgarh State Rural Employment Guarantee Council.
(6)	Chhattisgarh Gramin Sadak Vikas Abhikaran.
(7)	Chhattisgarh Gramin Garibi Unnulan Society.
(8)	Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy.
(9)	Shaskiya Kirodimal Polytechnic Society, Raigarh.
(10)	Karykari Samiti Chhattisgarh Vigyan Evam Padhdhogiki Parishad.
(11)	Rajya Vyavasayik Prashikshan Parishad, Chhattisgarh.
(12)	Rajya Shikshukta Parishad, Chhattisgarh.
(13)	Standing Committee constituted under the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Chhiniyam, 1994(No.21 of 1994).

(14)	State level Vigilance and Monitoring Committee constituted under the Chhattisgarh Anusuchit Jati Avam Janjati (Atyachar Nivaran) Niyam, 1995.
(15)	Chhattisgarh Adim Jati Mantrana Parishad (Tribal Advisory Council).
(16)	Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal.
(17)	Chhattisgarh Rajya Van Aushidhi Board.
(18)	Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA).
(19)	Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.
(20)	State Investment Promotion Board.
(21)	State Industry Advisory Board.
(22)	Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(23)	Sarguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(24)	Anusuchit Jati Vikas Pradhikaran.
(25)	State Planning Board.
(26)	Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society(CHIPS).
(27)	Chhattisgarh State Warehousing Corporation.
(28)	Chhattisgarh Tourism Board.
(29)	Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation Limited.
(30)	Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board.
(31)	Chhattisgarh State Council of Bhartat Scout and Guide.
(32)	Project Advisory Board of Integrated Tribal Development Project.
(33)	Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited.
(34)	Chhattisgarh Housing Board.
(35)	Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
(36)	Chhattisgarh Nishakt Jan Viita Avam Vikas Nigam.
(37)	Chhattisgarh State Legal Service Authority.
(38)	Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board.
(39)	Chhattisgarh Rajya Hathkargha Vikas Evam Vipnan Sahkari Sangh Maryadit.
(40)	Chhattisgarh Hastshilp Vikas Board.
(41)	Chhattisgarh Labour Welfare Board.
(42)	Chhattisgarh Shram Salahkar Parishad.
(43)	State Level Coordination Forum constituted under sub-section (4) of Section 166 of the Electricity Act, 2003.
(44)	Chhattisgarh Bio-Fuel Development Authority (CBDA).
(45)	Chhattisgarh Water Standing Committee.
(46)	State Flood Control Board.
(47)	Swashasi Samiti, Shaskiya Chikitsa Mahavidyalaya, Jagdalpur.
(48)	Swashasi Samiti, Shaskiya Dant Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.

(49)	Swasthasi Samiti, Pandit Jawahar Lal Nehru Smriti Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.
(50)	Swasthasi Samiti Ayurved Mahavidyalaya, Raipur.
(51)	Chhattisgarh Para-medical Council, Raipur.
(52)	Rajya Swasthya Mission.
(53)	Chhattisgarh Rajya AIDS Niyantaran Society.
(54)	Kushtha Rog Niyantaran Samiti.
(55)	Malaria Evam Filaria Niyantaran Samiti.
(56)	Rashtriya Drishtihcenta Nivaran Samiti.
(57)	Kshaya Rog Niyantaran Samiti.
(58)	Prajnan Shishu Swasthya Samiti.
(59)	Bahu Ayami Sanskritika Sansthan, Raipur.
(60)	Chhattisgarh Paryatan Salahkar Board.
(61)	Hotel Prabandhan Sansthan, Raipur.
(62)	Chhattisgarh Mahila Kosh.
(63)	State Social Welfare Board Chhattisgarh.
(64)	Chhattisgarh State Commission for Women.
(65)	Chhattisgarh Pathaya Pustak Nigam.
(66)	Chhattisgarh Madersa Board.
(67)	Chhattisgarh Rajya Sanskrit Board.
(68)	Chhattisgarh Rajya Saksharta Mission Pradhikaran.
(69)	Chhattisgarh Rajeev Gandhi Shiksha Mission.
(70)	Rajya Shahri Vikas Abhikaran.
(71)	Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Limited.
(72)	Chhattisgarh Rajya Beej Pramamikaran Sanstha.
(73)	Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.
(74)	Chhattisgarh Rajya Antyavasayi Sahakari Vitta Evam Vikas Nigam.
(75)	Chhattisgarh Rajya Wakfa Board.
(76)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog.
(77)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.
(78)	Chhattisgarh Rajya Pichhada Varga Ayog.
(79)	Chhattisgarh Rajya Ahi-Sakhayak Ayog.
(80)	Chhattisgarh Rajya Yuva Ayog.
(81)	Chhattisgarh Rajya Gau-Seva Ayog.
(82)	Chhattisgarh Arogya Chikitsa Shikshan Evam Anusandhan Samiti, Raipur.
(83)	Chhattisgarh Rajya Sahakari Matsya Mahasangh Maryadit.
(84)	Smt. Suryamukhi Devi Rajgammii Sampada Samiti (Nayas), Rajnandgaon.
(85)	Chhattisgarh Samvad.
(86)	Chhattisgarh Rajya Van Vikash Nigam.
(87)	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited.
(88)	Chhattisgarh State Wild Life Board.
(89)	Chhattisgarh Jaiv Vividhta Board.
(90)	Jeevan Deep Samiti of Government Hospital."

Special provision
as to validation.

6. (1) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the offices mentioned in the Schedule as amended by this Act, shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly as if the Principal Act, as amended by this Act, had been in force at all material times.

(2) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or other authority on the date of commencement of this Act, shall be disposed of in accordance with the provisions of the Principal Act, as amended by this Act.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019 — ज्येष्ठ 17, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.	1.	(1)	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.
		(2)	यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.
अनुसूची का संशोधन.	2.		छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
		“91	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, रायपुर
		92	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
		93	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित, रायपुर
		94	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
		95	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
		96	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर
		97	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
		98	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
		99	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
		100	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
		101	अटल नगर विकास प्राधिकरण
		102	छत्तीसगढ़ योग आयोग
		103	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
		104	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर
		105	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
		106	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

- 107 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, रायपुर
- 108 छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड
- 109 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
- 110 छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड
- 111 छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित
- 112 छत्तीसगढ़ सूख्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल
- 113 छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड
- 114 छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग
- 115 छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल
- 116 राज्य वित्त आयोग
- 117 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
- 118 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण
- 119 राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति
- 120 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
- 121 छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी
- 122 छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी
- 123 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर
- 124 छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, रायपुर
- 125 पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी सृजन पीठ, भिलाई
- 126 दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर
- 127 छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
- 128 तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड”

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2019)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.	1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. (2) It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st January, 2019.
Amendment of Schedule.	2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule, after serial number 90, the following shall be added, namely :- “91 Chhattisgarh Film Development Corporation, Raipur 92 State disaster Management Authority 93 Chhattisgarh Road Development Corporation Limited, Raipur 94 Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, Raipur 95 Chhattisgarh State Co-operative Association Limited, Raipur 96 District Cooperative Central Bank Limited, Raipur, Durg, Rajnandgaon, Jagdalpur, Bilaspur, Ambikapur 97 Chhattisgarh State Food Commission 98 Chhattisgarh Rajya Bal Adhikar Sanrakshan Ayog 99 Raipur Development Authority, Raipur 100 Chhattisgarh Environment Conservation Board 101 Atal Nagar Vikash Pradhikaran 102 Chhattisgarh Yoga Aayog 103 Chhattisgarh State Kesh Shilpi Welfare Board 104 Chhattisgarh State Medicinal Plants Board, Raipur 105 Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board 106 Chhattisgarh Unorgnized Workers State Social Security Board 107 Chhattisgarh Rajya krishak Kalyan Parishad, Raipur

- 108 Chhattisgarh Machua Kalyan Board
- 109 Chhattisgarh State Animal Welfare Board
- 110 Chhattisgarh Matikala Board
- 111 Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited
- 112 Chhattisgarh Micro and Small Enterprise Facilitation Council
- 113 Chhattisgarh Railway Corporation Ltd.
- 114 Chhattisgarh Rajya Shiksha Aayog
- 115 Chhattisgarh Professional Examination Board
- 116 State Finance Commission
- 117 Chhattisgarh State Cooperative Dairy Federation Limited
- 118 Chhattisgarh State Livestock Development Agency
- 119 State Level Twenty Point Implementation Review Committee
- 120 Chhattisgarh Rajya Gramin Avam Anya Pichhda Varg Kshetra Vikash Pradhikaran
- 121 Chhattisgarh State Haj Committee
- 122 Chhattisgarh Urdu Academy
- 123 Chhattisgarh Official Language Commission, Raipur
- 124 Chhattisgarh Sindhi Academy, Raipur
- 125 Padumlal-Punnalal Bakshi Shrijan Peeth, Bhilai
- 126 South Central Region Cultural Centre Nagpur
- 127 Chhattisgarh Sahitya Academy
- 128 Third Gender Welfare Board"

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2006

क्रमांक 13877/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव

CHHATTISGARH ACT (No. 30 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force retrospectively with effect from 1st November, 2000.

Definition: 2. In this Act, "Principal Act" means the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Amendment of Section 2. 3. After clause (b) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely:-

"(c) 'Compensatory Allowance' means any sum of money payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance, house rent allowance, communication allowance or any other allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office."

Amendment of Section 3. 4. For Section 3 of the Principal Act, the following Sections shall be substituted, namely,

"3. **Certain offices of profit not to disqualify**

It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule, in so far as it is an office of profit under the Government, shall disqualify or shall be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly.

3-A. Prevention of disqualification of certain offices Subject to the provisions of Section 3 no person holding the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director or Member of any

committee shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds such office:

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any remuneration other than compensatory allowance."

Amendment of Schedule.

5. In the Schedule to the Principal Act:-

(i) in item 8, for the words, figures, and bracket "Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898)" the words, figures and bracket "Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974)" shall be substituted.

(ii) For items 18 to 22, the following items shall be substituted, namely:-

"18. the office held by Chief Minister or Minister or Minister of State or Deputy Minister in ex-officio capacity.

19. the office of Chairman and Vice Chairman or President and Vice President or Director and Managing Director or Member Secretary or Secretary or Member of the following statutory body or committee: -

(1)	State Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995.
(2)	Rajya Shrot (Nishaktjan) Sanstham.
(3)	State Advisory Board constituted under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.
(4)	State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted for Rural Development Programmes.
(5)	Chhattisgarh State Rural Employment Guarantee Council.
(6)	Chhattisgarh Gramin Sadak Vikas Abhikaran.
(7)	Chhattisgarh Gramin Garibi Unmulan Society.
(8)	Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy.
(9)	Shaskiya Kirodimal Polytechnic Society, Raigarh.
(10)	Karykari Samiti Chhattisgarh Vigyan Evam Prodhogiki Parishad.
(11)	Rajya Vyavasayik Prashikshan Parishad, Chhattisgarh.
(12)	Rajya Shikshukta Parishad, Chhattisgarh.
(13)	Standing Committee constituted under the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(14)	State level Vigilance and Monitoring Committee constituted under the Chhattisgarh Anusuchit Jati Avam Janjati (Atyachar Nivaran) Niyam, 1995.
(15)	Chhattisgarh Adim Jati Mantrana Parishad (Tribal Advisory Council).
(16)	Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal.
(17)	Chhattisgarh Rajya Van Aushidhi Board.
(18)	Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA).
(19)	Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.
(20)	State Investment Promotion Board.
(21)	State Industry Advisory Board.
(22)	Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(23)	Sarguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.
(24)	Anusuchit Jati Vikas Pradhikaran.
(25)	State Planning Board.
(26)	Chhattisgarh Infotech and Biotech Promotion Society(CHIPS).
(27)	Chhattisgarh State Warehousing Corporation.
(28)	Chhattisgarh Tourism Board.
(29)	Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation Limited.
(30)	Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board.
(31)	Chhattisgarh State Council of Bhartat Scout and Guide.
(32)	Project Advisory Board of Integrated Tribal Development Project.
(33)	Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited.
(34)	Chhattisgarh Housing Board.
(35)	Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
(36)	Chhattisgarh Nishakt Jan Viita Avam Vikas Nigam.
(37)	Chhattisgarh State Legal Service Authority.
(38)	Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board.
(39)	Chhattisgarh Rajya Bankargha Vikas Evam Vipnan Sahkari Sangh Maryadit.
(40)	Chhattisgarh Hastshilp Vikas Board.
(41)	Chhattisgarh Labour Welfare Board.
(42)	Chhattisgarh Shram Salahkar Parishad.
(43)	State Level Coordination Forum constituted under sub-section (4) of Section 166 of the Electricity Act, 2003.
(44)	Chhattisgarh Bio-Fuel Development Authority (CBDA).
(45)	Chhattisgarh Water Standing Committee.
(46)	State Flood Control Board.
(47)	Swashasi Samiti, Shaskiya Chikitsa Mahavidyalaya, Jagdalpur.
(48)	Swashasi Samiti, Shaskiya Dant Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.

(49)	Swasthasi Samiti, Pandit Jawahar Lal Nehru Smriti Chikitsa Mahavidyalaya, Raipur.
(50)	Swasthasi Samiti Ayurved Mahavidyalaya, Raipur.
(51)	Chhattisgarh Para-medical Council, Raipur.
(52)	Rajya Swasthya Mission.
(53)	Chhattisgarh Rajya AIDS Niyantaran Society.
(54)	Kushtha Rog Niyantaran Samiti.
(55)	Malaria Evam Filaria Niyantaran Samiti.
(56)	Rashtriya Drishtiheenta Nivaran Samiti.
(57)	Kshaya Rog Niyantaran Samiti.
(58)	Prajnan Shishu Swasthya Samiti.
(59)	Bahu Ayami Sanskritika Samsthan, Raipur.
(60)	Chhattisgarh Paryatan Salahkar Board.
(61)	Hotel Prabandhan Samsthan, Raipur.
(62)	Chhattisgarh Mahila Kosh.
(63)	State Social Welfare Board Chhattisgarh.
(64)	Chhattisgarh State Commission for Women.
(65)	Chhattisgarh Pathaya Pustak Nigam.
(66)	Chhattisgarh Madarsa Board.
(67)	Chhattisgarh Rajya Sanskrit Board.
(68)	Chhattisgarh Rajya Saksharta Mission Pradhikaran.
(69)	Chhattisgarh Rajeev Gandhi Shiksha Mission.
(70)	Rajya Shahri Vikas Abhikaran.
(71)	Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Limited.
(72)	Chhattisgarh Rajya Beej Pramanikaran Samstha.
(73)	Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.
(74)	Chhattisgarh Rajya Antyavasayi Sahakari Vitta Evam Vikas Nigam.
(75)	Chhattisgarh Rajya Wakfa Board.
(76)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jan Jati Ayog.
(77)	Chhattisgarh Rajya Anusuchit Jati Ayog.
(78)	Chhattisgarh Rajya Pichhoda Varga Ayog.
(79)	Chhattisgarh Rajya Aik-Sakhayak Ayog.
(80)	Chhattisgarh Rajya Yuva Ayog.
(81)	Chhattisgarh Rajya Gaurav Ayog.
(82)	Chhattisgarh Arogya Chikitsa Shikshan Evam Anusandhan Samiti, Raipur.
(83)	Chhattisgarh Rajya Sahkari Matsya Mahasangh Maryadit.
(84)	Smt. Suryamukhi Devi Rajganmi Sampada Samiti (Nayas), Rajnandgaon.
(85)	Chhattisgarh Samvad.
(86)	Chhattisgarh Rajya Van Vikash Nigam.
(87)	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited.
(88)	Chhattisgarh State Wild Life Board.
(89)	Chhattisgarh Jaiv Vividhta Board.
(90)	Jeevan Deep Samiti of Government Hospital."

Special provision
as to validation.

6. (1) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the officers mentioned in the Schedule as amended by this Act, shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being a member of the Chhattisgarh Legislative Assembly as if the Principal Act, as amended by this Act, had been in force at all material times.

(2) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any petition or reference pending before any court or other authority on the date of commencement of this Act, shall be disposed of in accordance with the provisions of the Principal Act, as amended by this Act.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019 — ज्येष्ठ 17, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.	1.	(1)	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.
		(2)	यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.
अनुसूची का संशोधन.	2.		छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
		“91	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, रायपुर
		92	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
		93	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित, रायपुर
		94	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
		95	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
		96	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर
		97	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
		98	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
		99	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
		100	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
		101	अटल नगर विकास प्राधिकरण
		102	छत्तीसगढ़ योग आयोग
		103	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
		104	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर
		105	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
		106	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

- 107 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, रायपुर
- 108 छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड
- 109 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
- 110 छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड
- 111 छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित
- 112 छत्तीसगढ़ सूख्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल
- 113 छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड
- 114 छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग
- 115 छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल
- 116 राज्य वित्त आयोग
- 117 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
- 118 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण
- 119 राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति
- 120 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
- 121 छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी
- 122 छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी
- 123 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर
- 124 छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, रायपुर
- 125 पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी सृजन पीठ, भिलाई
- 126 दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर
- 127 छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
- 128 तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड”

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2019

क्रमांक 5746/डी. 111/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2019)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.	1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. (2) It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st January, 2019.
Amendment of Schedule.	2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule, after serial number 90, the following shall be added, namely :- “91 Chhattisgarh Film Development Corporation, Raipur 92 State disaster Management Authority 93 Chhattisgarh Road Development Corporation Limited, Raipur 94 Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, Raipur 95 Chhattisgarh State Co-operative Association Limited, Raipur 96 District Cooperative Central Bank Limited, Raipur, Durg, Rajnandgaon, Jagdalpur, Bilaspur, Ambikapur 97 Chhattisgarh State Food Commission 98 Chhattisgarh Rajya Bal Adhikar Sanrakshan Ayog 99 Raipur Development Authority, Raipur 100 Chhattisgarh Environment Conservation Board 101 Atal Nagar Vikash Pradhikaran 102 Chhattisgarh Yoga Aayog 103 Chhattisgarh State Kesh Shilpi Welfare Board 104 Chhattisgarh State Medicinal Plants Board, Raipur 105 Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board 106 Chhattisgarh Unorgnized Workers State Social Security Board 107 Chhattisgarh Rajya krishak Kalyan Parishad, Raipur

- 108 Chhattisgarh Machua Kalyan Board
- 109 Chhattisgarh State Animal Welfare Board
- 110 Chhattisgarh Matikala Board
- 111 Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited
- 112 Chhattisgarh Micro and Small Enterprise Facilitation Council
- 113 Chhattisgarh Railway Corporation Ltd.
- 114 Chhattisgarh Rajya Shiksha Aayog
- 115 Chhattisgarh Professional Examination Board
- 116 State Finance Commission
- 117 Chhattisgarh State Cooperative Dairy Federation Limited
- 118 Chhattisgarh State Livestock Development Agency
- 119 State Level Twenty Point Implementation Review Committee
- 120 Chhattisgarh Rajya Gramin Avam Anya Pichhda Varg Kshetra Vikash Pradhikaran
- 121 Chhattisgarh State Haj Committee
- 122 Chhattisgarh Urdu Academy
- 123 Chhattisgarh Official Language Commission, Raipur
- 124 Chhattisgarh Sindhi Academy, Raipur
- 125 Padumlal-Punnalal Bakshi Shrijan Peeth, Bhilai
- 126 South Central Region Cultural Centre Nagpur
- 127 Chhattisgarh Sahitya Academy
- 128 Third Gender Welfare Board"

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 902]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 — पौष 7, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|-----------------------|---------|----|---|
| संक्षिप्त
प्रारंभ. | नाम तथा | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 कहलाएगा.</p> <p>(2) यह 1 अगस्त, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.</p> |
| अनुसूची का संशोधन. | | 2. | <p>छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, -</p> <p>(एक) सरल क्रमांक 22 में, शब्द “बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” के स्थान पर, शब्द “बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” प्रतिस्थापित किया जाये;</p> <p>(दो) सरल क्रमांक 23 में, शब्द “सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” के स्थान पर, शब्द “सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण” प्रतिस्थापित किया जाये; और</p> <p>(तीन) सरल क्रमांक 128 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-</p> <p>“129 छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण.</p> <p>130. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.”</p> |

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्रमांक 13360/डी. 235/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 of 2019)

**THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall be deemed to have come in to force retrospectively with effect from 1st August, 2019. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule,- | Amendment of Schedule. |
| | (i) | in serial number 22, for the words “Bastar Evam Dakshin Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran”, the words “Bastar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran” shall be substituted; | |
| | (ii) | in serial number 23, for the words “Surguja Evam Uttar Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran”, the words “Surguja Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran” shall be substituted; and | |
| | (iii) | after serial number 128, the following shall be added, namely :- | |
| | | “129. Chhattisgarh Sports Development Authority. | |
| | | 130. Madhya Kshetra Adiwasi Vikas Pradhikaran.” | |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021 — आश्विन 5, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|----------------------------|----|-----|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा. |
| | | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| अनुसूची का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 130 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- |

“131. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड.”

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-9-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 16 of 2021)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN

(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in the table of item 19 of the Schedule, after serial number 130, the following shall be added, namely :- | Amendment of Schedule. |
| | | “131. Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited.” | |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2023 — श्रावण 25, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. 9978/डी. 79/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 11-08-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 16 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलाएगा।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल क्रमांक 25 में, शब्द "राज्य योजना मंडल" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. 9978/डी. 79/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 16-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2023)

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in serial number 25 of the table of item 19 of the Schedule, for the words “State Planning Board”, the words “State Planning Commission” shall be substituted. | Amendment of Schedule. |